पर्यावरण कानूनों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं : पीएम

प्रेट्र • नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का किया समर्थन

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि हरित क्षेत्रों का नुकसान रोकने के लिए पर्यावरण मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाइसेंस परमिट राज व्यवस्था फिर से नहीं लौटनी चाहिए।

दिल्ली सतत विकास सम्मेलन-2011 के उद्घाटन के मौके पर गुरुवार को उन्होंने इस सिद्धांत का भी समर्थन किया कि प्रदूषण फैलाने वाले (उद्योगों) से इसकी कीमत वसूली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे उचित सिद्धांत यही है कि सतत विकास के लिए आर्थिक फैसले लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पर्यावरण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच प्रोजेक्टों को मंजूरी देने को लेकर ठनी हुई है। नो गो क्षेत्र में खनन की इजाजत नहीं देने के कारण कोयला मंत्रालय तो पर्यावरण मंत्रालय की खुले में आलोचना करता रहा है। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश कह चुके हैं कि वे विकास के नाम पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी नहीं होने देंगे। सम्मेलन में पीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानक बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू करना काफी कठिन काम है। सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई सहित कई विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के लिए कोई अलग कानून हैं। लेकिन एक सामान्य नियम के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण फैलाने वालों को पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा योगदान देना चाहिए।